यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2019–22/114/2020 **दिनांक** : 08.07.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

एलआईसी बचाओ दिवस – 14 जुलाई, 2020 को

उपरोक्त विषय में हम एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 28/214/2020/52 दिनांक 8.7.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना, संज्ञान एवं अनुपालन हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

एलआईसी बचाओ दिवस – 14 जुलाई, 2020
एआईएलआईसीईएफ द्वारा राष्ट्रीय अभियान – समर्थन प्रदान करें

हमारी यूनियनों और सदस्यों को ज्ञात है कि सरकार द्वारा घोषित हाल के आर्थिक उपायों के भाग के रूप में, सरकार ने एलआईसी में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने के माध्यम से एलआईसी के निजीकरण के अपने फैसले के साथ एलआईसी की पूंजी को कम करने का निर्णय लिया है।

एलआईसी हमारे देश में एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्था है जो पिछले छह दशकों से अधिक में बनी है। यह आम लोगों की विशाल और बहुमूल्य बचत का प्रतिनिधित्व करती है। एलआईसी का निजीकरण और इसमें विनिवेश का निर्णय बहुत अविवेकपूर्ण निर्णय है, लेकिन वर्तमान सरकार आगे बढ़ने पर तुली हुई है।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) को इस महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र निगम में विनिवेश का काम सौंपा गया है। यह पहले से ही परामर्श केन्द्रों, निवेश बैंकरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बोलियों से निपटने में लगा हुआ है। **बोलियां 14 जुलाई को खोली जानी हैं।** यह एलआईसी को मारने की अवांछित प्रक्रिया की शुरूआत होगी।

इसलिए एलआईसी में हमारे भ्रात्रीय संगठन, ऑल इंडिया एलआईसी इम्प्लाईज फैडरेशन ने इस अनुचित कदम का विरोध करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।

अभियान के एक भाग के रूप में, **एआईएलआईसीईएफ 14 जुलाई को एलआईसी बचाओ दिवस के रूप में मना रही है।**

वे 11 जुलाई (शनिवार) को सायं 5:00 बजे अपने फेसबुक के माध्यम से एक राष्ट्रीय वेबिनार का भी आयोजन कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री को एक ऑनलाईन याचिका भी आयोजित कर रहे हैं।

हाल ही में, हमने उनकी पदाधिकारियों की बैठक में भाग लिया और उनके अभियान और कार्यक्रमों के प्रति हमारे समर्थन और एकजुटता का आश्वासन दिया।

हम अपनी सभी यूनियनों का आह्वान करते हैं कि उनके अभियान को अपना समर्थन दें। हमारे सभी सदस्य प्रधानमंत्री को याचिका (प्रतिपृष्ठ पर) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अपनी एकजुटता व्यक्त कर सकते हैं।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह... **सी.एच. वेंकटचलम्**
महामंत्री

PETITION TO PRIME MINISTER

The proposed Disinvestment in LIC goes against the policy of Aatmanirbhar Bharat.

Disinvestment in LIC will be a stepping stone for privatisation in future which will be against the national interest.

LIC of India since its inception in 1956 has been spearheading the spread of life insurance to the vast majority of the populace and in particular to the rural areas and to the socially and economically backward classes with a view to reach all insurable persons in the country and providing them adequate financial cover against death at a reasonable cost.

True to the objective of nationalisation, the Corporation has mobilized the funds invested by the people in the life insurance for the benefit of the community at large.

National priorities and obligation of reasonable returns to the policyholders have been the main criteria of LIC's investment.

The total funds, so invested for the benefits of the community at large are Rs 29,84,331 crore as on 31st March 2019.

The proposed public offer through disinvestment in LIC will change the way surplus is distributed. Higher share of surplus to shareholders will affect the rate of bonus to policyholders and this in turn will affect future new business.

Listing of LIC will also change LIC's operational approach and investment policies.

LIC was establishing with the prime objective to mobilise money for infrastructure development, protecting the policyholders' interest and at the same time spreading life insurance at a low cost to the common man.

LIC has always been at the service of the people and nation and attempts to disinvest in LIC will change the Corporation motive from service to profit making and the aim will be to maximise the return to its shareholders.

This will also discourage LIC from providing insurance coverage to the underprivileged section of the society.

In order to survive the cut throat competition LIC may be pushed to review its investments in the social sectors like housing, power, irrigation, water supply, sewerage, road, port & bridges, railways and other infrastructure investment.

We want LIC for a better India, developed India. Selling LIC is against the idea of Aatmanirbhar India. It's like killing the goose which is laying golden eggs.

We the undersigned call upon the Honourable Prime Minister of India to rescind the decision of disinvesting in LIC in national interest. Selling LIC is against the idea of Aatmanirbhar India.

Use the following link to send the online Petition to Prime Minister

https://www.change.org/p/prime-minister-of-india-stop-the-listing-of-lic-for-an-aatmanirbhar-india? recruiter= 701239211& utm_source= share_petition &utm_medium= copylink &utm_campaign= share_petition&utm_term=57ff6ec871d24bfabc0f37fd43dbcb29

click the link and submit your petition. Forward the link to your friends and contacts